(d) Government of West Bengal has informed that per MW cost at 1996 level without IDC comes to Rs. 3.51 crores. At the time of commissionig the per MW cost is estimated to be Rs. 3.64 crores (with IDC). This however, is not comparable with cost per MW of coal based private sector fast track projects which are cleared by CEA on a completed cost basis and different financing structure.

नई दिल्ली के नानकपुरा क्षेत्र में भूमि का अतिक्रमण, अवैध खरीद-फरोख्त तथा निर्माण

1209. **श्री जलालुदीन अंसारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित नानकपुरा में खसरा नं॰ 224,225 में सरकारी भूमि, मोटर-गाड़ियां खड़ी करने की जगह तथा पटरियों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के आयुक्त द्वारा लिखित चेतावनी दिए जाने के बाद भी सरकारी भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त जारी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में तहखानों तथा बहु मंजिला इमारतों का अवैध निर्माण भी हो रहा है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपर्युक्त क्षेत्र में अवैध कब्जों तथा तहखानों के निर्माण को रोकने हेतु दो सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए हुए हैं; और

(ङ) यदि हो, तो सरकार इस संबंध मे कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालस में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेश्वरलु): (क) नानकपुरा, नई दिल्ली में खसरा नं॰ 224 और 225 की भूमि, डी॰डी॰ए॰ की नजुल-। भूमि है सरकारी भूमि नहीं, लेकिन कार पार्किंग और फुटपाथ क्षेत्र पर अतिक्रमण होता रहा है।

(ख) अवैध बिक्री/खरीद का कोई मामला डी॰डी॰ए॰ के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, डी॰डी॰ए॰ ने इस इलाके में बोर्ड लगायें हैं जिन पर लिखा हुआ है कि प्रश्नगत जमीन प्राधिकरण की है।

(ग) जी, हां। बेसमेंट और बहुमंजिले भवनों का अवैध निर्माण आंशिक रूप में डी॰डी॰ए॰ की जमीन पर है।

(घ) जी, हां। डी॰ डी॰ ए॰ भूमि की निगरानी व सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते है।

(ङ) डी॰डी॰ए॰ ने अगस्त, 1996 के शुरू में इस स्थान पर अनाधिकृत निर्माण को गिराने/अतिक्रमण को हटाने का कार्यक्रम रखा है।

कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

1210. **श्री मुलचन्द मीणा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले पर आधारित राज्य-वार कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई है और इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या राजस्थान के धौलपुर जिले हेतु एक विद्युत संयंत्र की स्वीकृति दी गई थी, यदि हां, तो इस संयंत्र को वहां अभी तक स्थापित न करने के क्या कारण है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) देश में कोयले पर आधारित स्वीकृत और निष्पादनाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। (**देखिए परिशिष्ट सं. 178, अनुपत्र संख्या 31**)

(ख) और (ग) राजस्थान के धौलपुर जिले में ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने की किसी योजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है।

Power Projects in Karnataka

1211. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of power projects under execution in Karnataka as on the 30th June, 1996 with the cost thereof and the assistance to be provided by the Central Government;

(b) the details of private sector projects;

(c) the total power likely to be generated as a result thereof; and

(d) by when these projects are likely to be commissioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a), (c) & (d) Details of power projects in Karnataka which are